

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 65
TO BE ANSWERED ON 08/12/2023

IMPACT OF PBW ON COTTON PRODUCTION

*65. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) in what manner Government looks at dwindling cotton production from 566 kgs/hectare in 2013-14 to 445 kgs/hectare in 2022-23;
- (b) to what extent Pink Boll-Worm (PBW) is impacting cotton production in the country, including Andhra Pradesh;
- (c) whether it is a fact that PBW was earlier seen only in Southern States but has now spread across the country and impacting production; and
- (d) if so, efforts made by the Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC) of Government to address this menace and see that cotton production goes up again?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 65 DUE FOR REPLY ON 08/12/2023 REGARDING “IMPACT OF PBW ON COTTON PRODUCTION”.

(a): The production of cotton has been fluctuating over the years depending upon weather conditions, irrigation facilities, soil conditions, pest & diseases, etc. However, the country is self-sufficient in cotton production & surplus cotton is exported after meeting the domestic requirement. During 2022-23, the production of cotton was 336.60 lakh bales against consumption of 311 lakh bales. Further, the Department of Agriculture & Farmers Welfare is implementing cotton development programme under National Food Security Mission (NFSM) in 15 major cotton growing states to increase production and productivity from 2014-15.

A special project on cotton entitled ‘Targeting technologies to agro-ecological zones- large scale demonstrations of best practices to enhance cotton productivity’ has been approved under NFSM during 2023-24.

The Government has been increasing the Minimum Support Prices (MSP) of cotton over the years to encourage farmers for cultivation of cotton and ensure remunerative prices. During the year 2023-24, MSP for medium staple cotton and long staple cotton has increased to Rs. 6620/ quintal & Rs. 7020/quintal respectively, which is 8.9% & 10% higher than previous year.

Total 247 varieties/hybrids have been released and notified in India during 2014 till now which include both from public & private sector. Among these 247 varieties/hybrids, 125 are non-Bt cotton & 122 are Bt cotton. Further, cotton crop is also being notified by the various States against comprehensive risks including pests/diseases under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).

(b) & (c): Pink Bollworm infestation is seen in all the cotton growing areas of North, Central & South Zone across the country. However, as per survey conducted by ICAR-Central Institute for Cotton Research (CICR), Nagpur, the infestation of pink bollworm has reduced from 30.62% during 2017-18 to 10.80% during 2022-23. Further, the infestation of pink bollworm in Andhra Pradesh has reduced from 39% during 2017-18 to 8.81% during 2022-23.

(d): Central Insecticide Board & Registration Committee (CIB&RC) is a regulatory body for processing of application for grant of registration of insecticides. CIB&RC has granted the registration of 50 insecticide formulations for the control of pink bollworm & bollworm complex. Further, CIB&RC has also granted the registration of pheromone [PB Rope L (Gossyplure) pheromone dispenser] to monitor & trap the pink bollworm population.

Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage (DPPQ&S) regularly issues advisories for management of pink bollworm. Further, Farmer Field School (FFS) on cotton crop are being conducted on adoption of Integrated Pest Management (IPM) approaches for management of pink bollworm.

A project titled 'Insecticide Resistance Management (IRM): Dissemination of Pink Bollworm Management Strategies' has been approved by Government of India since 2018-19 under NFSM with an objective to disseminate Pink Bollworm Management Strategies integrating several multiple strategies during different growth stages of cotton crop to combat it.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 65
8 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: पीबीडब्ल्यू का कपास के उत्पादन पर प्रभाव

***65. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार कपास के घटते हुए उत्पादन, जो वर्ष 2013-14 में 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2022-23 में 445 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है, को किस प्रकार देखती है;

(ख) पिक बॉलवॉर्म (पीबीडब्ल्यू) आंध्र प्रदेश सहित देश में कपास उत्पादन को किस सीमा तक प्रभावित कर रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि पीबीडब्ल्यू पहले केवल दक्षिणी राज्यों में देखा जाता था लेकिन अब यह देश-भर में फैल गया है और पैदावार को प्रभावित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबीआरसी) द्वारा इस खतरे से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि कपास का उत्पादन फिर से बढ़े?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“पीबीडब्ल्यू का कपास के उत्पादन पर प्रभाव” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 08.12.2023 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 65 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) : मौसम की दशाओं, सिंचाई सुविधाओं, मृदा की स्थिति, कीट और रोगों आदि के आधार पर कपास के उत्पादन में वर्षों से उतार-चढ़ाव आता रहा है। तथापि, देश कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद अधिशेष कपास का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कपास का उत्पादन 311 लाख गांठ की खपत के सापेक्ष 336.60 लाख गांठ था। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एनएफएसएम के तहत कपास पर “टार्गेटिंग टेक्नोलोजीज टु एग्रो-इकोलोजिकल जोन्स - लार्ज स्केल डिमोन्स्ट्रेशन्स ऑफ बेस्ट प्रेक्टिसेस टु इन्हांस कॉटन प्रोडक्टिविटी” नामक एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी गई है।

सरकार किसानों को कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करती रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान, मध्यम स्टेपल कपास और लंबे स्टेपल कपास का एमएसपी बढ़ाकर क्रमशः 6620 रुपये/क्विंटल और 7020 रुपये/क्विंटल किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% और 10% अधिक है।

वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारत में कुल 247 किस्में/संकर जारी और अधिसूचित किए गए हैं जिनमें सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इन 247 किस्मों/संकरों में से 125 गैर-बीटी कपास हैं और 122 बीटी कपास हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों द्वारा कपास की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत नाशीजीवों/रोगों सहित व्यापक जोखिमों के खिलाफ भी अधिसूचित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : पिक बॉलवार्म का संक्रमण देश भर के उत्तर, मध्य और दक्षिण क्षेत्र के सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में देखा गया है। तथापि, आईसीएआर- केंद्रीय कपास

अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पिक बॉलवार्म का संक्रमण वर्ष 2017-18 के दौरान 30.62% से कम होकर वर्ष 2022-23 के दौरान 10.80% हो गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में पिक बॉलवॉर्म का संक्रमण वर्ष 2017-18 के दौरान 39% से घटकर वर्ष 2022-23 के दौरान 8.81% हो गया है।

(घ) : केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) कीटनाशकों के पंजीकरण की अनुमित हेतु अनुप्रयोग के प्रसंस्करण के लिए नियामक निकाय है। सीआईबी एंड आरसी ने पिक बॉलवॉर्म और बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स के नियंत्रण हेतु 50 कीटनाशक फॉर्मूलेशन के पंजीकरण की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, सीआईबी एंड आरसी ने पिक बॉलवार्म की संख्या की निगरानी एवं रोकथाम के लिए फेरोमोन [पीबी रोप एल (गॉसीप्लर) फेरोमोन डिस्पेंसर] के पंजीकरण की भी अनुमति दी है।

वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस) पिक बॉलवार्म के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से सलाह जारी करता है। इसके अलावा, पिक बॉलवॉर्म के प्रबंधन हेतु एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए कपास की फसल पर किसान फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित किए जा रहे हैं।

कपास फसल के विभिन्न विकास चरणों के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान की दृष्टि से कई बहु-कार्यनीतियों को एकीकृत करते हुए पिक बॉलवार्म प्रबंधन कार्यनीतियों का प्रसार करने के उद्देश्य से एनएफएसएम के तहत वर्ष 2018-19 से भारत सरकार द्वारा 'इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट (आईआरएम) : डिसेमिनेशन ऑफ पिक बॉलवार्म मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज' नामक परियोजना को अनुमति दी गई है।

श्री अनिल प्रसाद हेगडे: माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है कि भारत की seed market में जो Bt Cotton technology उपलब्ध है, वह पिंक बाल-वॉर्म के लिए resistant है और Monsanto-Bayer जैसी बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बीज कंपनियाँ द्वारा पिंक बाल-वॉर्म इंफेस्टेशन के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों को कितना पैसा देकर compensate किया गया और कौन-कौन सी प्रदेश सरकारों ने उन्हें इस चीज़ के लिए compensate किया है?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पिंक बाल-वॉर्म की बात कही है, उसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किए हैं कि नई varieties तैयार की हैं। ICAR के द्वारा इस पर लगातार प्रयास करके कई वैराइटीज़ तैयार की गई हैं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि भविष्य में इसका समाधान भी हो, तो मैं उन्हें निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह कह सकता हूँ कि पिंक बाल-वॉर्म की एक वजह यह है कि जब जुलाई में बरसात आती है, तो यह उसी समय आता है। इसकी shelf life लगभग तीन, साढ़े तीन महीने से लेकर चार महीने रहती है, इसलिए इसकी समस्या लास्ट में सामने आती है, लेकिन इसके समाधान के लिए ICAR की तरफ से लगातार प्रयास करके वैराइटीज़ तैयार की जा रही हैं।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, this PB-knot technology is being tested in Kurnool district of Andhra Pradesh, which is tested to effectively kill Pink Boll-Worm. I would like to know as to whether the Government of India has got the plan of action to provide it and if at all there are plans to distribute it, then the hon. Minister may provide the details.

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सभापति, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमने कुछ वैराइटीज़ तैयार की हैं और हम इसके साथ ही किसानों को कुछ एडवाइज़री भी जारी करते हैं। इसी का परिणाम है कि जो एडवाइज़री जारी करके उन्हें बताया जाता है, उससे नुकसान में कटौती हो रही है। 2017-18 में पिंक बाल-वॉर्म बीमारी की वजह से लगभग 30 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ था, जो अब घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह गया है यानी कि हमने इसके माध्यम से 30 प्रतिशत नुकसान की कटौती की है। हमारे साइंटिस्ट्स वहाँ जाकर जो demonstration देते हैं और एडवाइज़री जारी करते हैं, उसके अनुसार यदि किसान उस सीड पर समय पर fertilizer का छिड़काव करते हैं, तो इससे उनकी फसल का बचाव जरूर होता है। ये सारी जानकारियाँ देने की वजह से ही इसमें 30 परसेंट की कमी आई है। हमारा आगे भी लगातार यह प्रयास है कि इसमें और कटौती आए। महोदय, अगर कोई पौधा है, तो उसमें स्वतः ही कहीं न कहीं से कोई बीमारी आती है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि उसका समाधान कैसे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए निश्चित रूप से वैराइटीज़ भी हैं और जो pesticides हैं, उनको भी नए-नए तरीके से लाकर इस समस्या का समाधान करें - इस पर सरकार का कार्य लगातार चालू है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 66. Shri Shaktisinh Gohil; not present. Any supplementaries?